

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

17/8/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपरिथत। विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता उपरिथत। शेष विप्रार्थी अनुपरिथत। उभयपक्ष अधिवक्ताओ की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका रिथति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हरतगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम भिण्डा कुआं तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 5,19,28,29, 31,63,74, 79,80,82, 89,90,91, 93,95, 96,97,98,99,100,101,115,116,117,128,129,130,134,135,136 कुल रकबा 177.11 बीघा भूमि के संबध में मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभय-पक्षकारान को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) जालोर